



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593]  
No. 593]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2006/अग्रहायण 24, 1928  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2006/AGRAHAYANA 24, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2006

(आयकर)

सा. का. नि. 757(अ).—जबकि आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम हेतु भारत गणराज्य की सरकार तथा नार्वे किंगडम के बीच अभिसमय, उक्त अभिसमय को प्रवृत्त करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को उनके अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने पर अधिसूचना के बाद वर्ष 1986 अर्थात् वह वर्ष जिसमें यह हस्ताक्षरित किया गया था, में प्रवृत्त हुआ ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश दिया कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (विदेश कर प्रभाग) की दिनांक 9 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 756(अ) के साथ संलग्न उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में प्रभावी बनाए जायेंगे;

और जबकि उक्त अभिसमय में रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद भारत और एक तीसरे देश के बीच किसी अभिसमय अथवा करार के अन्तर्गत भारत को रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के

लिए फीस पर अपने कराधान को आय की कथित मदों पर वर्तमान करार में उपबोधित दर की अपेक्षा न्यूनतर दर पर सीमित करना चाहिए तब आय की कथित मदों पर उक्त अभिसमय अथवा करार में यथा-उपबोधित वही दर इस अभिसमय के अन्तर्गत भी लागू होगी;

और जबकि 9 सितम्बर, 2004 को प्रवृत्त हुए भारत और अर्मीनिया के मध्य, 15 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए भारत और सूडान के मध्य तथा 4 मार्च, 2005 को प्रवृत्त हंगरी के साथ हुए करारों ने तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क एवं रॉयल्टियों पर स्रोत पर कराधान को आय की उक्त मदों पर भारत एवं नार्वे के मध्य करार में विहित की गई दर से निम्न दर पर सीमित कर दिया है ;

इसलिए अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (विदेश कर प्रभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 1987 में भारत में 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होने वाले एवं नार्वे में 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी होने वाले निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :

आय एवं पूंजी कर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य एवं नार्वे किंगडम के मध्य करार से संबंधित परिशिष्ट में उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 13 के पैरा 2 में "20 प्रतिशत से अधिक नहीं" शब्दों एवं अंकों की जगह "10 प्रतिशत से अधिक नहीं" शब्द और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए।

[अधिसूचना सं. 368/2006-विदेश कर प्रभाग/

फा. सं. 505/3ए/81-विदेश कर प्रभाग]

डी. पी. सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2006

**(INCOME-TAX)**

**G.S.R. 757(E).**—Whereas the Convention between the Government of the Republic of India and the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital came into force in the year 1986, being the year in which it was signed, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force the said Convention;

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 44A of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957), Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and Section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), had directed that all the provisions of the said Convention annexed to the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), (Foreign Tax Division) number G.S.R.756 (E) dated the 9th September, 1987 shall be given effect to in the Union of India;

And whereas the aforesaid Convention, under paragraph 2 of Article 13 relating to Royalties and fees for technical services, provides that if after the entry into force of this Convention, under any Convention or Agreement between India and a third State, India should limit its taxation on royalties or fees for technical services to a rate lower

than that provided for in the present agreement on the said items of income, then, the same rate as provided for in that Convention or Agreement on the said items of income shall also apply under this Convention;

And whereas the Conventions between India and Armenia, which came into force on the 9th September, 2004, India and Sudan which came into force on the 15th April, 2004 and Hungary which came into force on the 4th March, 2005, have limited the taxation at source on royalties and fees for technical services to a rate lower than that provided in the Convention between India and Norway on the said items of income;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), (Foreign Tax Division) number G.S.R.756 (E) dated the 9th September, 1987, with effect from the 1st April, 2006, in India and with effect from 1st January, 2006, in Norway, namely :—

In the said notification, in the Annexure, relating to the Convention between the Republic of India and the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, in Article 13, in paragraph 2 for the words and figures “not exceed 20 percent” the words and figures “not exceed 10 percent” shall be substituted.

[Notification No. 368/2006-FTD/F. No. 505/3A/81-FTD]

D. P. SENGUPTA, Jt. Secy.